भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1133
08 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारिता आंदोलन

1133. श्री रतन लाल कटारिया

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गुजरात में सहकारिता आंदोलन एक सफल प्रयोग रहा है और क्या सरकार ने कुछ मंत्रालयों में सहकारी नीतियों को लागू करने की घोषणा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का इज़राइल और जापान की तर्ज पर भारत में सहकारी नीति लागू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार सहकारिता को समाजवाद और पूंजीवाद के विकल्प के रूप में देखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): गुजरात सहित देश के कई राज्य सहकारिता आधारित कई कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं। अमुल, इफको, कृभको और नेफेड सफल प्रयोगों के कुछ उदाहरण हैं। सरकार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की नीतियों में सहकारिता को प्राथमिकता देने का इरादा रखती है।

(ख): फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

(ग): सहकारी समितियां देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं और समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। ये सदस्यों द्वारा संचालित और लोकतांत्रिक रूप से शासित लोक संस्थाएं स्वयं-सहायता और पारस्परिक-सहायता के सिद्धांतों पर आधारित हैं जो उन्हें अपने स्वयं के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।